

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2143

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 09 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट

2143. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) इस तरह के मूल्यहास का व्यापार और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर दिनांक 31 दिसंबर 2014 को ₹63.04/अमेरिकी डॉलर और दिनांक 03 दिसंबर 2024 को ₹84.70/अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष 2014 से कैलेंडर वर्ष के अंत तक आगे की विनिमय दर के मूल्य नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

दिनांक	अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपये विनिमय दर	वार्षिक परिवर्तन (%)
31-दिसंबर-14	63.04	
31-दिसंबर-15	66.15	-4.70%
30-दिसंबर-16	67.93	-2.62%
29-दिसंबर-17	63.87	6.36%
31-दिसंबर-18	69.77	-8.46%
31-दिसंबर-19	71.38	-2.26%
31-दिसंबर-20	73.07	-2.31%
31-दिसंबर-21	74.34	-1.71%
30-दिसंबर-22	82.74	-10.15%
29-दिसंबर-23	83.21	-0.56%
03-दिसंबर-24	84.70	-1.76% [#]
#दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 तक		

(ख) भारतीय रुपये का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है, जिसका कोई लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं होता है। भारतीय रुपये की विनिमय दर को डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव, पूंजी प्रवाह के रुझान, ब्याज दरों का स्तर, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, चालू खाता घाटा आदि जैसे विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारक प्रभावित करते हैं। चालू कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान, भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन का मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर की व्यापक-आधार पर मजबूती है, जिसने उभरती बाजार मुद्राओं पर दबाव डाला है। इसके अलावा, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं।

(ग) मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, अवमूल्यन से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। तथापि, घरेलू कीमतों पर विनिमय दर में गिरावट का समग्र प्रभाव अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों के घरेलू बाजार में लागू होने की सीमा पर निर्भर करता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में आयात भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति, व्यापार योग्य वस्तुओं की प्रकृति (अर्थात् आवश्यक या सुख-सुविधा की वस्तुएं), माल ढुलाई लागत, वैकल्पिक वस्तुओं की उपलब्धता आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, आयात और घरेलू मुद्रास्फीति पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया भर में होने वाले उन प्रमुख घटनाक्रमों पर नज़र रखता है जिनका अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपये के विनिमय दर पर असर पड़ सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें प्रमुख सेंट्रल बैंकों की मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई, विश्व भर में जारी किए जाने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़े और उनके प्रभाव, ओपेक+ बैठक के निर्णय, भू-राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखना और उनका विश्लेषण करना, जी-10 और ईएमई मुद्राओं में दैनिक उतार-चढ़ाव आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार को उसके व्यवस्थित कामकाज और विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियंत्रित करता है और भारतीय रुपये में होने वाले अनावश्यक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए ही हस्तक्षेप करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने और उनका विस्तार करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, ताकि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को और वैश्विक स्तर पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इंकीमेंटल फोरेन करेंसी नॉन रेजीडेंट (बैंक) एफसीएनआर(बी) तथा नॉन रेजीडेंट (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमा देयताओं को दिनांक 04 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमाराशियों के लिए सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट प्रदान की गई है। नई एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाराशियों को दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक ब्याज दरों (ब्याज दरें बैंकों द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए) पर मौजूदा विनियम से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण अंतर्वाह में एफपीआई निवेश से संबंधित विनियामक व्यवस्था को संशोधित किया गया है। विदेशी वाणिज्यिक उधार सीमा (ऑटोमेटिक रूट के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया और दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में कुल लागत सीमा को 100 बीपीएस तक बढ़ा दिया गया। एडी कैट-1 बैंक विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर यथा लागू एंड यूज प्रेस्क्रिप्शन हेतु विदेशी मुद्रा में उधार देने के लिए विदेशी मुद्रा उधार का उपयोग कर सकते हैं।